नाथू ला दर्रा : चीनका उद्देश्य सिर्फ व्यापार नहीं

भारतकी चीनसे लगी सिक्किमकी सीमाके रास्ते शुरू हुए नये व्यापारिक सम्पर्कके पीछे चीनका उद्देश्य सिर्फ व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाना नहीं है, क्योंकि चीनको यो भी अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करनेके लिए भारतसे नजदीकी बढ़ानेकी कोई जरूरत नहीं है। आज चीन दुनियाके आर्थिक क्षितिजकों क नयी दिशा देनेवाली हैसियतमें है और यूरोपके सारे समृद्ध देश इसका लोहा मान चुके हैं। चीनने ऐसे समयमें भारतसे व्यापारिक सम्बन्ध मजबूत करनेकी पेशकश की है, जब सीमा विवाद सुलझानेके लिए सारी वार्ताए विफल साबित हो चुकी हैं और ये ऐसे विवाद हैं जो १९६२ से चले आ रहे हैं, जब प्रधान मन्त्री जवाहरलाल नेहरूको झांसा देकर चीनने भारतपर हमला किया और भारतीय सैनिकोंको खदेड़ते हुए भारतके कई इलाकोंपर कब्जा कर लिया। अगर नेहरूने अमेरिकासे मदद न ली होती तो चीनसे लगे भारतके तमाम सीमावर्ती इलाकोंपर चीन अधिकार कर लेता।

सिक्किमका नाथू ला वही दर्रा है जो १९६२ में बन्द हो गया था। आज ४४ वर्ष बाद इस रास्तेसे भारतकी सीमामें फिरसे प्रवेशका आखिर असली मकशद क्या है? इसके साथ-साथ एक और सवाल उठता है कि पर्यटकोंके बहाने व्यापार बढ़ानेके लिए चनीने सिक्किमको ही क्यों चुना। जबकि पूर्वोत्तरसे लेकर कश्मीरतक भारतके कई इलाके चीनकी सीमासे सटे हैं। कुछ दिन पहले म्यांमार और बंगलादेशसे सड़क और रेल सम्पर्क मार्ग सुदृढ़ करनेके लिए चीनने जो योजना बनायी उसके बारेमें भारतसे पूछा भी नहीं। वह समझैता बिल्कुल गुप्त रखा गया, जबकि वह सड़क पूर्वोत्तरकी सीमाके बिल्कुल करीबसे गुजरती है। नाथू-ला सम्पर्क सूत्रको समझनेके लिए सिक्किमके उस राजनीतिक पहलुओंका विश्लेषण करना होगा जो चीनसे जुड़ा है। सबसे पहले यह स्पष्ट करना जरूरी है कि सिक्किमका १९७५ में प्रधान मन्त्री इंदिरा गांधी द्वारा भारतमें विलय चीनने स्वीकार नहीं किया और इस योग्यता रियासतको भारतके राज्यके रूपमें मान्यता नहीं दी। १९७५ से लेकर २००६ तक चीन सिक्किमको अपना एक हिस्सा बताता रहा। अभी भी गुगल नेटपर सिक्किमको चीनके प्रान्तके रूपमें देखा जा सकता है। वो चीनका आफिसियल नक्शा है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अभी अचानक सिक्किमको भारतीय प्रान्त मान लेते (हालांकि इस आशयका कोईइ लिखित समझौता नहीं हुआ है और सिक्किमके मुख्य मन्त्री पवन कुमार चामलिंग तथा पश्चिम बंगालके मुख्य मन्त्री बुद्धदेव भट्टाचार्यसे केन्द्रसे अलग हटकर अन्तरंगता बढ़ानेके पीछे अवश्य ही चीनके व्यापारके अलावे भी कुछ इरादे हैं।

सिक्किमकी संस्कृति, रहन-सहन, सभ्यता काफी कुछ चीनसे मिलती-जुलती है। चोग्यालकी चीन अपना भाई मानता था और चाहता था कि वो भारतीय सीमामें एक अलग अस्तित्व बनाये रखकर चीनके साथ रहे। योग्याल द्वारा चीनकी उम्मीदोंपर पानी फेर दिये जानेके बावजूद चीन निराश नहीं हुआ और सिक्किमके लगभग सभी मुख्यमन्त्रियों (नर बहादुर भंडारीसे लेकर चामलिंग तक) ने चीनके प्रति नरम रवैया रखा। नाथू-ला को खोलनेके लिए पड़ोसी पश्चिम बंगालकी वामपंथी सरकार कई वर्षोंसे प्रयत्नशील थी और आखिरकार बुद्धदेव भट्टाचार्यने इस काममें काफी दिलचस्पी ली। इनकी रूचि लेनेकी वजह तो कम्युनिस्ट सरकारका होना सहज ही समझमें आनेवाला है। लेकिनव यह मामला सिर्फ सिक्किम और पश्चिम बंगालके चीनसे जुड़नेका नहीं है। वैसे केन्द्रकी कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन सरकार यदा-कदा चीनको खुश करनेके लिए अपने वामपंथी घटके सांसदोंको बीजिंग दौरेपर भेजती रहती है। नेपालमें भी माओवादियोंकी जीतके बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीके पोलित ब्यूरो सदस्य सीताराम येचुरी काठमांडू गये। लेकिन चीनसे सम्बन्धित मुद्देका सीधा ताल्लुक भारतकी सुरक्षासे है और यह सरोकार ऐसे समयमें चालू हुआ है, जब तिब्बतको रेल सम्पर्कसे जोड़नेका काम चीन पूरा कर चुका है। आज चीन इस स्थितिमें है कि तिब्बत, पूर्वोत्तर और नेपाल समेत किसी भी रास्तेसे अपनी सैनिक टुकड़ी मिनटोंमें सिक्किममें उतार सकता है। गंगटोकके मुहाने उत्तर पूर्वी राज्योंसे मिलते हैं जहां सक्रिय लगभग सारे विद्रोही गुटोंका एक पैर म्यांमार और दूसरा पैर बंगलादेशमें है। म्यामारकी सैनिक सरकार मुख्यरूपसे चीनी मददपर टिकी है। चीनने म्यांमारके साथ इसी बीच हथियारोंके बदले इमारती लकड़ी और चावलका समझौता किया है। म्यांमारकी भी भारत नीति चीनसे मिलती जुलती है। पिछले वर्ष म्यांमारके सीनियर जनरल थान श्वेने दिल्ली आकर पूर्वोत्तरके विद्रोहियोंको अपनी जमीनसे भारत विरोधी गतिविधियां न चलानेका आश्वासन दिया। लेकिन एनएससीएन (नेशनल सोसलिस्ट कौंसिल आफ नगालैण्ड) के खपलांग गुटका अड्डा आज भी म्यांमारमें मौजूद हैं, जिसके साथ केन्द्र सरकारका युद्ध विराम समझौता सात वर्षोंसे चल रहा है।

अप्रैल, १९६० में चीनके प्रधान मन्त्री चाउ एन लाई सीमा-सम्बन्धी विवादके बारेमें बात करने दिल्ली आये। पंडित नेहरूने उनसे नेफाकी उत्तरी सीमाके रूपमें मैकमोहन रेखाको स्वीकारनेका आग्रह किया। चाउने इसपर तो कोई आपत्ति नहीं की, मगर साथमें अस्काई चीनमें चीनी फौजकी मौजूदगी चाही। नेहरूको इसमें कोई रुचि नीहं थी। नेहरूने संसदको बताया कि चीनके साथ सारे मतभेद दूरकर लिये गये हैं। और दो साल बीतते-न बीतते चीनने नेफाको भारतीय सैनिकोंसे मुक्त करा लिया। इस घटनाके आगे-पीछे भी जाना आवश्यक है। चाउ-एन-लाई काठमांडु, कराची, काबुल होते हुए दिल्ली आये थे और उनके लौटनेके बाद नेपालके प्रधान मन्त्री टंका प्रसाद आचार्यने पेकिंग जाकर नेपाल-चीन भाई-भाईका नारा दिया। वे भी पाकस्तिान होते हुए स्वदेश लौटे। भारतकी तुलनामें चीनकी दोगुनी फौज नाथू-लाकी भारतीय सीमाकी ४५४५ मीटर ऊंची पहाड़ीपर मौजूद हगैं। चीनकी कूटनीतिका आलम देखिये कि जिस दलाई लामाको उनकी तिब्बत समेत तहत-नहस करनेमें वहांकी कम्युनिस्ट तानाशाहीने कोई कसर नहीं छोडी है, उनके ७१ वें जन्मदिन (६ जुलाई) पर खासतौरसे गंगटोकमें जश्नके साथ व्यापारिक सम्पर्क खोलनेकी पुख्ता बातचीत हुई। सिल्क व्यापारका रूट खुल जानेके साथ-साथ चामलिंग इस बातसे भी खुश हैं कि नाथू-ला तिब्बत जानेका सबसे आसान और कम समय लगनेवाला रास्ता है। उनके मुताबिक नेपाल-कोलकाताके जरिये २००० किलोमीटरकी दूरी तय करनी होती है जबकि नाथू-ला दर्रेसे होकर मात्र १४०० किलोमीटर जाना होता है। बौद्ध प्रदेश सिक्किमके मुख्य मन्त्री अपने यहांके पर्यटकोंको तिब्बतके छुम्बी घाटीमें बेरोकटोक जानेका सपना देख रहे हैं। १६ जुलाईको आयोजित समारोहमें चीनी राजदूत सुन यूशीके लौटनेके बाद चामलिंगको स्पष्ट करना पड़ा कि सिक्किमकी जनताने स्वेच्छासे भारतमें विलय स्वीकार किया था। इसका मतलब है कि सिक्किमको लेकर चीन और भारतके मनमें पड़ी गांठको ढीला करनेके चला रहे हैं। हिमालय (शिपकिला) और उत्तरांचल (लिपुलेशव)वाले रास्ते आंशिक रूपमें १९९० के दशकमें खुल गये थे। (सप्रेस)

❑ शशिधर खां

अन्तराल

सिक्किमका नाथू ला वही दर्रा है जो १९६२ में बन्द हो गया था। आज ४४ वर्ष बाद इस रास्तेसे भारतकी सीमामें फिरसे प्रवेशका आखिर असली मकशद क्या है? इसके साथ-साथ एक और सवाल उठता है कि पर्यटकोंके बहाने व्यापार बढ़ानेके लिए चीनने सिक्किमको ही क्यों चुना। जबकि पूर्वोत्तरसे लेकर कश्मीरतक भारतके कई इलाके चीनकी सीमासे सटे हैं। कुछ दिन पहले म्यांमार और बंगलादेशसे सड़क और रेल सम्पर्क मार्ग सुदृढ़ करनेके लिए चीनने जो योजना बनायी उसके बारेमें भारतसे पूछा भी नहीं। वह समझैता बिल्कुल गुप्त रखा गया, जबकि वह सड़क पूर्वोत्तरकी सीमाके बिल्कुल करीबसे गुजरती है।

10 अक्टूबर 2006
3105